

राजस्थान पत्रिका

पत्रिका

Page 2, 27th September, 2021

एनएफएसयू में स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज की शुरुआत

अब साइबर घटनाओं में न्याय प्राप्त करना होगा आसान : मंत्री रिजिजू

प्रशिक्षित, तकनीकी
जानकार कानूनी
विशेषज्ञ उपलब्ध
कराएगी एनएफएसयू

अहमदाबाद @ पत्रिका. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनएफएसयू में स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज के निर्माण से डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनेगा। जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया भी आसान और त्वरित बनेगी और अंततः 'ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस' यानी न्याय प्राप्त करने में आसानी की संकल्पना साकार होगी। वे रविवार को गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक



साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) में स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा कि इस स्कूल से देश को टेक्नो लीगल एक्सपर्ट के रूप में तकनीक से लैस विशेषज्ञों का मानवबल उपलब्ध होगा। गुजरात के कानून एवं न्याय मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि यूनिवर्सिटी विभिन्न पाठ्यक्रम के जरिए पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर रही हैं। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के

न्यायाधीश एम.आर. शाह, गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आर.एम. छाया, राज्य के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी तथा राज्य उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति, न्यायविद, विद्यार्थी और आमंत्रित उपस्थित थे। एनएफएसयू के कुलपति जे.एन. व्यास ने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के निर्माण को साकार करने के लिए कदम उठा रही हैं। पांच प्रोग्राम के साथ शुरू हुई यूनिवर्सिटी में आज सत्तर प्रोग्राम हैं।

कानूनी ज्ञान युक्त
मानवबल की

जरूरत: जस्टिस शाह

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.आर. शाह ने कहा कि आज राष्ट्र को कानूनी ज्ञान और अभ्यास युक्त मानव बल की जरूरत है, जो यह स्कूल के जरिए पूरा होगा। अब, विधि क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन गया है। इस स्कूल के विद्यार्थियों को आने वाले कल का वकील और कानूनी सलाहकार बताते हुए एम.आर. शाह ने कहा कि राष्ट्र हित का दायित्व इन विद्यार्थियों के सिर पर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्र के आम नागरिकों की समस्याओं का संतोषजनक निवारण करने में इस यूनिवर्सिटी में चल रहे पाठ्यक्रम सहायक होंगे।

दैनिक जागरण

Page 3, 27th September, 2021

न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका में कोई टकराव नहीं : किरण रिजिजू

गांधीनगर, प्रेटर : न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान की खबरों के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इनके बीच कोई टकराव नहीं है। लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच जीवंत संबंध महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ईज आफ टूइंग विजनेस और ईज आफ लिविंग की तरह ईज आफ जस्टिस की भी बात की जानी चाहिए।

रविवार को नए स्कूल आफ ला, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज का उद्घाटन करने के बाद गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि जज जो कहते और सोचते हैं, केंद्र सरकार को उसे अमल में लाना चाहिए और ऐसा केवल कोर्ट की अवमानना के डर से नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग-अलग अंग हैं, लेकिन हम सभी देश के लिए काम करते हैं। बाहर के लोग सोचते हैं कि हमारे बीच टकराव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं।

सरकार का रुख

कहा, सभी कर रहे राष्ट्र के लिए कार्य, इनके बीच जीवंत संबंध महत्वपूर्ण

ईज आफ टूइंग विजनेस, ईज आफ लिविंग की तरह हो ईज आफ न्याय



किरण रिजिजू।

फाइल/इंटरनेट मीडिया

देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर आफ इंडिया का उद्घाटन

किरण रिजिजू ने अहमदाबाद में देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर आफ इंडिया (एसएसीआई) का उद्घाटन किया। यह एक स्वतंत्र पंचाट होगा जो खेल से जुड़े विवाद का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि इसकी देश के खेल क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिसे कानून एवं न्याय मंत्रालय से पूरी मदद मुहैया कराई जाएगी।

रिजिजू ने कहा कि जज जो भी कहते या सोचते हैं, उसे लागू करना हमारा काम है। यह कार्यपालिका का काम है कि वह कोर्ट के फैसले को अच्छे ढंग से लागू करे। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कानूनों को लागू नहीं किए जाने की धारणा को मोदी सरकार में काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। रिजिजू ने कहा कि जजों से तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वे तभी तारीफ करेंगे जब हम अच्छा काम

करेंगे। उन्होंने जजों को आश्वासित किया कि सरकार पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करेगी।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एमआर शाह, गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश आरएम छाया और कई वरिष्ठ सेवानिवृत्त जज मौजूद थे।

First India

Page 1, 27th September, 2021

'TROUBLESHOOTING'

FROM PG 1

Troubled politicians use judges as cover: Rijiju

First India Bureau

Gandhinagar: Union Minister for Justice and Law Kiren Rijiju on Sunday made a statement regarding politicians, and how they often used judges as shields when in trouble. Hailing the democratic system of government, he also said that its three organs—the judiciary, executive and legislature—must function together in the interest of the nation.

Rijiju was in Gandhinagar to inaugurate the School of Law, Forensic Justice and Policy Stud-

ies at the National Forensic Sciences University (NFSU) campus.



Other dignitaries at the event included Supreme Court Justice MR Shah, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Acting Guja-

rat High Court Chief Justice R M Chhaya, Gujarat Law Minister Rajendra Trivedi, and Minister of State for Home Harsh Sanghavi.

Rijiju also said that it was the duty of the executive wing to implement judgements of the courts, but that it should not come through due to fear of contempt of court. He also shared his grievances and expressed concern over the fact that laws passed by the legislature were not being implemented. "I have high hopes

Turn to P6

Troubled... that with the technology at hand, courts will soon be able to dispense justice at the litigants' doors, and they will not be required to head from one court to another," he said.

On the new courses offered by NFSU, CM Patel said, "The new courses introduced will provide technological legal experts to the society and the judiciary, which will help in fast delivery of justice to the people.

The pattern and modus of crime has changed with time, which can be addressed only by the use of technology."

Echoing a similar sentiment, state Law Minister Trivedi, asserted, "With technological inventions, crime has increased. An upgradation of knowledge with technology is needed and if new courses like these are introduced then it will benefit the justice system."

No turf war between three pillars of democracy: Rijiju

TIMES NEWS NETWORK

Gandhinagar: Union minister for law and justice **Kiren Rijiju** said here on Sunday



that there is no turf war between the executive, legislature and judiciary and that all three are working in the interests of the nation. Rijiju said this while inaugurating the School of Law, Forensic Justice and Policy Studies at Gujarat Forensic Sciences University (GFSU).

"The judiciary, executive and legislature are different organs but all are working for the country. People outside feel there is a turf war. There is nothing like that. We all are

working for the interest of the nation," said the Union minister, adding, "I have told the Chief Justice, when I became new law minister, Whenever you phone me. As the law minister of this country, I am always ready in the service of judges and judiciary. We will have to function in this manner."

Expressing contentment at the presence of many judges at the function, the minister quipped, "Today, so many judges are present here. I am really happy. At times when we face difficulties and cannot get things done politically, we place judges at the forefront. When judges are at the forefront, things get done fast. So many judges being present here is a good sign."

Commenting on the role of the government, the minister

said, "In the Supreme Court, high courts and even in the lower judiciary, there are judgments or we get to listen to commentaries of judges during (court) hearings, and even anguish and satisfaction aired by them. It is our duty to implement whatever judges say," the minister said.

"There is a need for a lively relation between organs of government. In a democracy, it is very important for us to have a lively relation between us (the judiciary, executive and legislature)...It is vital for us to have a lively relationship," the minister said.

Rijiju further said the "impression" that laws are not being implemented for a long time has been removed to a great extent under the Narendra Modi government.

Hindustan Times

Page 5, 27th September, 2021



Kiren Rijju

RIJJU: NO TURF WAR BETWEEN THE JUDICIARY, EXECUTIVE AND LEGISLATURE

Press Trust of India

letters@hindustantimes.com

GANDHINAGAR : A lively relationship between the judiciary, the legislature and the executive is vital in a democracy, Union law minister Kiren Rijju said here on Sunday even as he dismissed the perception of any turf war among these three organs.

Speaking at the Gandhinagar-based National Forensic Sciences University (NFSU) after inaugurating the new School of Law, Forensic Justice and Policy Studies, Rijju said "it is for the government to implement whatever judges say and think and this should not be done out of fear for the contempt of court alone". "The judiciary, the executive and the legislature are separate organs, but we all work for the country. People on the outside think we are engaged in a turf war, fighting for a domain, but that is not the case. We all are working for the interest of the nation," Rijju said.

"In the Supreme Court, high courts and even in the lower judiciary, we get to listen to commentaries of judges during (court) hearings, and even anguish and satisfaction aired by them through the media. It is for us to implement whatever judges say or think," the minister said.

Rijju said it was for the executive to "judiciously implement" a good judgment of the court of law. "In a democracy, it is very important for us to have a lively relation between us (the judiciary, executive and legislature)...It is vital for us to have a lively relationship," he said.

Rijiju: No turf war between judiciary, legislative, executive



Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju in Gandhinagar Sunday, *Express*

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 26

THERE IS no "turf war" between the judiciary, legislature and executive in the country, said Union Minister of Law and Justice Kiren Rijiju on Sunday, adding that the central government was willing to work hard to earn judges' praises.

"The judiciary, executive and legislature are different organs, but we work together for the country. At times, people from outside think there is a turf war or fight going on over the domain... There's nothing like that. We are all working for the interest of the nation," the minister said at the inauguration of the School of Law, Forensic Justice and Policy Studies at the National Forensic Sciences University (NFSU) Gandhinagar.

"Whenever we are in trouble or we are not able to do our job as politicians, we bring judges forward. Work gets done easier when judges are at the front... When I was appointed the law and justice minister, I told the Chief Justice of India that whenever you call me as a law minister

CONTINUED ON PAGE 4

The Indian EXPRESS

JOURNALISM OF COURAGE

Page 1, 27th September, 2021

No turf war between judiciary, legislative and executive: Rijiju

of the country, I am always ready for the services of the judges and the judiciary. Whenever we see an issue in the Supreme Court, high court or lower courts, there are times we are able to listen to the commentary during hearing or judgements," Rijiju said.

Saying that fear for contempt of court should not be the only reason behind implementing good judgements, the minister added, "In the legislature, whenever we make laws on paper, we are also frustrated that they are not implemented swiftly. But now due to the visionary leadership of PM Modi, that environment is long gone. The word aaram (relaxation) is no longer

in our dictionary."

"If we all work proactively, then the judiciary will also not taunt us and they will also appreciate the government's work. Judges will say good about us only when we do good. I assure all the judges here that our government will work with all our heart and with transparency," Rijiju said at the event where Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Minister of State for Home Harsh Sanghavi, SC judge Justice MR Shah, acting Chief Justice of Gujarat High Court Justice RM Chhaya and Gujarat Law and justice minister Rajendra Trivedi were also present.

The Gandhinagar-based

NFSU will offer two programmes – a five-year integrated BSC plus LLB Honours course (post Class 12) and a three-year LLB Honours course (post-graduation) under the newly inaugurated School of Law, Forensic Justice and Policy Studies.

Speaking at the event, CM Bhupendra Patel said the school will provide techno-legal experts who will be equipped with state-of-the-art technology. "As the nature of crime has changed, it will enable the justice delivery system to tackle the current challenges with the help of forensic sciences and also facilitate to provide evidence in

courts. It will also offer employment opportunities to the youth," he said.

NFSU Gandhinagar Vice-Chancellor Dr JM Vyas said, "We are following the vision of PM Modi... we started with five courses, and today we have over 70 courses. We are also opening our campuses and training centres in different states of the country. Forensic sciences play an extremely crucial role in the criminal justice delivery system and in that regard, our university is attempting to cover the three aspects of this system which include legal aspect, forensic sciences and policing and security."